



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 भाद्र 1935 (श0)
(सं0 पटना 692) पटना, बुधवार, 4 सितम्बर 2013

सं0 03-39/2007-803

गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

संकल्प

3 सितम्बर 2013

विषय:-श्री शिवदयाल राय, पुनर्स्थापित (Re-instated) सहायक लोक अभियोजक को विभागीय संकल्प सं0 647 दिनांक 17.07.2013 की कंडिका-11 (घ) में उल्लेखित अवधि दिनांक 16.07.1996 से सेवानिवृति की तिथि अर्थात् 31.07.08 तक की अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में विनियमित करते हुए इस अवधि को पेंशन हेतु गणना करने संबंधी आदेश को संशोधित करते हुए दिनांक 16.07.1996 से 31.07.08 तक की अवधि का वेतनादि भुगतान करने के संबंध में ।

अभियोजन निदेशालय के पत्रांक 1116 दिनांक 13.12.1991 द्वारा श्री शिवदयाल राय, तत्कालीन सहायक लोक अभियोजक, सदर कोर्ट, पटना के विरुद्ध प्रतिवेदित घोर अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता, उदण्डता, कदाचार एवं वरीय पदाधिकारियों के साथ गलत आचरण तथा उनके आदेश का उल्लंघन करने, अपने पद का दुरुपयोग तथा सरकारी मुकद्दों में सही ढंग से पैरवी नहीं करने आदि संबंधी आरोप एवं तदनुरूप उसके आलोक में विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने संबंधी प्राप्त अनुशंसा के आलोक में गृह (आ0) विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या 102 दिनांक 09.01.1992 द्वारा उपर्युक्त आरोपों के लिए श्री राय को आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित किया गया। साथ ही, गृह (आ0) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञाप सं0 293 दिनांक 27.01.1992 द्वारा श्री राय को आरोप पत्र उपलब्ध कराते हुए सिविल सेवा

(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 55 के अधीन उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई गयी तथा संकल्प सं० 8950 दिनांक 28.09.1992 द्वारा निलंबित सहायक लोक अभियोजक श्री राय के विरुद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 55 के अधीन विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।

2. श्री शिवदयाल राय द्वारा निलम्बन आदेश एवं विभागीय कार्यवाही निरस्त करने एवं कुछ कागजात उपलब्ध कराने हेतु माननीय पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं० 1525/94 दायर किया गया जिसमें माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा श्री राय के निलंबन आदेश को रद्द करते हुए 10 सप्ताह के अन्दर विभागीय कार्यवाही को पूर्ण करने का आदेश दिनांक 21.07.1995 को पारित किया गया।

3. माननीय पटना उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के आलोक में गृह (आ०) विभाग के आदेश ज्ञापांक 7444 दिनांक 16.09.1995 द्वारा गृह (आ०) विभाग के आदेश संख्या-102 दिनांक 09.01.1992 द्वारा निलंबित सहायक लोक अभियोजक श्री शिवदयाल राय को तत्कालिक प्रभाव से निलंबन से मुक्त करते हुए निलंबन अवधि के संबंध में विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के पश्चात् निर्णय लेने के संबंध में निर्णय लिया गया।

4. गृह (आ०) विभाग के संकल्प संख्या-4275 दिनांक 23.04.1996 द्वारा श्री राय के विरुद्ध संचालित इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु नियुक्त संचालन पदाधिकारी श्री रविकांत, अपर सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना के पत्रांक 767 दिनांक 10.05.1996 द्वारा श्री राय के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए पत्रांक 4796 दिनांक 11.05.1996 द्वारा श्री शिवदयाल राय से द्वितीय कारणपृच्छा मांगी गई।

5. श्री शिवदयाल राय, सहायक लोक अभियोजक, सदर कोर्ट पटना के विरुद्ध अनुशासनहीनता, कदाचार एवं प्रशासनिक कार्यों में दखलंदाजी के आरोप में बर्खास्तगी के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करने हेतु गृह (आ०) विभाग के पत्रांक 5185 दिनांक 20.05.1996, पत्रांक 6809 दिनांक 26.06.1996, पत्रांक 7132 दिनांक 04.07.1996 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से अनुरोध किया गया किन्तु आयोग की सहमति ससमय प्राप्त नहीं हुई।

6. गृह (आ०) विभाग के संकल्प सं० 7835 दिनांक 16.07.1996 द्वारा श्री शिवदयाल राय के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के जॉच प्रतिवेदन एवं श्री राय से प्राप्त लिखित बचाव की सम्यक समीक्षा के उपरांत उनके विरुद्ध गंभीर कर्तव्यहीनता, उत्तरदायित्व का पूर्ण अभाव, प्रशासनिक अक्षमता, अशिष्ट व्यवहार, उच्छृंखलता एवं कदाचार के गंभीर आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण श्री राय को संकल्प के निर्गत होने की तिथि से सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया एवं निलंबन अवधि में श्री राय को जीवन निर्वाह भत्ता के अलावे और कुछ भी राशि भुगतान नहीं करने का भी निर्णय लिया गया।

7. श्री राय की बर्खास्तगी आदेश पर दिनांक 26.06.1996 को मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त की गई। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 1443 दिनांक 14.11.1996 द्वारा श्री राय की बर्खास्तगी के प्रस्ताव पर घटनोत्तर सहमति प्रदान की गई।

8. श्री शिवदयाल राय द्वारा बर्खास्तगी आदेश संकल्प सं० 7835 दिनांक 16.07.1996 को रद्द करने हेतु माननीय पटना उच्च न्यायालय में CWJC No. 8207/96 दायर किया गया, जिसमें सुनवाई के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.09.2007 को इनके बर्खास्तगी आदेश को रद्द करते हुए निम्न आदेश पारित किया गया-

“Accordingly Resolution dated 16-07-1996 contained in Memo No. 7835, dismissing the petitioner from the post of Assistant public prosecutor is quashed. The respondents are directed to give all the consequential benefit due to the petitioner with increments for the period 05-01-1992 to 05-01-1996, to pay full salary for the period 09-01-1992 to 16-09-1995 after deducting the S.A, Re-instate the petitioner and give all the consequential benefit.”

9. CWJC No. 8207/96 में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.09.2007 को पारित आदेश के विरुद्ध सरकार द्वारा माननीय पटना उच्च

न्यायालय में LPA No. 160/2008 दायर किया गया। पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.09.2012 को LPA No. 160/2008 को खारिज करते हुए निम्नवत् आदेश पारित किया गया है—

“Having considered the entire facts and circumstances, we find no good reasons to interfere with the order of the learned single judge. The appeal is found to be without merit. It is dismissed accordingly. There shall be no order as to costs.”

10. माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा LPA No. 160/2008 में दिनांक 24.09.2012 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में S.L.P (Civil) cc 7527/2013 दायर किया गया जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.04.2013 खारिज करते हुए निम्न आदेश पारित किया गया है—

“We see no reason to interfere. The special leave petition is dismissed.”

11. माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 8207/1996 शिवदयाल राय एवं अन्य में दिनांक 27.09.07 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु निम्न प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु उपस्थापित किया गया :-

(क) श्री शिवदयाल राय की बर्खास्तगी संबंधी निर्गत आदेश विभागीय संकल्प संख्या 7835 दिनांक 16.07.1996 को निर्गत की तिथि से निरस्त करते हुए उन्हें सेवा में पुनर्स्थापित (Re-instate) किया जाय।

(ख) उन्हें दिनांक 05.01.1992 से 05.01.1996 तक की वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाय।

(ग) उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता घटाकर दिनांक 09.01.1992 से 16.09.1995 तक के पूर्ण वेतन का भुगतान किया जाय।

(घ) दिनांक 16.07.1996 से श्री शिवदयाल राय की सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात् 31.07.2008 तक की अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में विनियमित करते हुए इस अवधि को पेंशन हेतु गणना की जाय।

12. विभागीय प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के पश्चात विभागीय संकल्प सं0 647 दि0 17.07.13 द्वारा निम्न स्वीकृति प्रदान की गयी :-

(क) श्री शिवदयाल राय की बर्खास्तगी संबंधी निर्गत आदेश विभागीय संकल्प संख्या 7835 दिनांक 16.07.1996 को निर्गत की तिथि से निरस्त करते हुए उन्हें सेवा में पुनर्स्थापित किया जाता है।

(ख) उन्हें दिनांक 05.01.1992 से 05.01.1996 तक की वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी।

(ग) उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता घटाकर दिनांक 09.01.1992 से 16.09.1995 तक का पूर्ण वेतन देय होगा।

(घ) दिनांक 16.07.1996 से श्री शिवदयाल राय की सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात् 31.07.2008 तक की अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में विनियमित किया जाता है तथा इस अवधि की पेंशन हेतु गणना की जायगी।

13. पुनः न्यायिक आदेश के आलोक में संकल्प सं0 647 दिनांक 17.07.13 की कंडिका 11 (घ) के संदर्भ में विधि विभाग से “शिवदयाल राय को सेवा में पुनर्स्थापित करने की तिथि 16.07.96 से सेवानिवृत्ति की तिथि 31.07.08 तक की

अवधि का पूर्ण वेतन भुगतान करना आवश्यक है या नहीं ?” के बिंदु पर परामर्श प्राप्त किया गया। इस बिंदु पर विधि विभाग द्वारा निम्नलिखित परामर्श दिया गया :-

“In my opinion, the order is to the effect that the writ petitioner is to be allowed, all benefits including the salary and increment till the date of his retirement and the order contained in Memo No. 624, dated 11-07-2013 is not in true spirit and consonance of the order passed by the Hon’ble Court.”

14. अतः इस मामले में विधि विभाग से प्राप्त उपर्युक्त परामर्श के आलोक में विभागीय संकल्प सं० 647 दिनांक 17.07.2013 की कंडिका-11(घ) को संशोधित करने का निम्नरूपेण निर्णय लिया जाता है-

दिनांक 16.07.1996 से श्री शिवदयाल राय की सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात् 31.07.08 तक की अवधि का वार्षिक वेतन वृद्धि सहित पूर्ण वेतन देय होगा।

आदेश-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में तुरंत प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

आमिर सुबहानी,

सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 692-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>